देश-विदेश में ''राजस्थान फाउंडेशन'' का दायरा बढ़ा, अब 51 चैप्टर - भजनलाल

मुख्यमंत्री के प्रभाव से गत तीन वर्ष में 39 चैप्टर नए बनाए गए

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ''राजस्थान फाउंडेशन'' के विस्तार से विश्व भर में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद, समन्वय और सहभागिता को नई गति मिलेगी।

जयपुर, 25 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए पिछले 3 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस क्रम में, प्रवासियों के लिए नए विभाग का गठन, राजस्थान फाउंडेशन द्वारा नए चैप्टर का गठन, जिलों में प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन, प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासियों के साथ निरंतर संवाद, देश-विदेश में प्रवासी मीट सहित, कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।

राजस्थान फाउंडेशन का नेटवर्क अब 51 चैप्टर तक विस्तारित हो गया है। इनमें 25 राष्ट्रीय और 26 अंतरराष्ट्रीय चैप्टर शामिल हैं। वर्ष 2023 में राजस्थान फाउंडेशन के केवल 12 चैप्टर थे तथा वे भी क्रियाशील नहीं थे। इन सभी को क्रियाशील करने के साथ ही, पिछले तीन वर्षों में 39 नए चैप्टर बनाए गए हैं।

राजस्थान फाउंडेशन द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के साथ जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए नए चैप्टर्स का



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।

निरंतर विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16 अक्टूबर, 2026 को प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम के दौरान 11 नए चैप्टर गठित करने की घोषणा की थी। इन सभी चैप्टर्स के गठन तथा अध्यक्षों के मनोनयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राजस्थान फाउंडेशन के विस्तार से विश्वभर में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद, समन्वय और सहभागिता को नई गति मिलेगी। इससे प्रवासी समुदाय को राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और निवेश संबंधी विकास कार्यों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। इन चैप्टर्स के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों के बीच मजबूत नेटवर्क विकसित होगा। इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान, निवेश प्रोत्साहन, कौशल एवं तकनीकी सहयोग, शिक्षा, पर्यटन तथा समाजसेवा के क्षेत्रों में नई संभावनाओं का विस्तार होगा।

दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी

- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की।

नई दिल्ली, 25 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की ओर से दाखिल नयी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। शरजील इमाम और उमर खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को इन दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि उच्च, न्यायालय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बंधा है और न्यायिक अनुशासन का पालन करना जरूरी है।

इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

पंचायती राज चुनाव परिणाम भाजपा के खिलाफ जनादेश हैं - सचिन पायलट

पायलट ने पंचायती राज में जीत को पूरी टीम राजस्थान की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बुधवार को अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले तथा मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का श्रेय देते हुए कहा कि यह जीत राजस्थान की सामूहिक मेहनत का परिणाम है।

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पंजाब में कृषि कानूनों और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अलग हुए भाजपा व अकाली दल अब सत्ता के लिए फिर साथ आ गए हैं।

जयपुर, 25 नवंबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पंचायतीराज चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को जनता की जीत बताते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। बुधवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा के अहंकार और नाकामियों का जवाब दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का सूपड़ा साफ होना प्रदेश की तीन साल की सरकार और केन्द्र की डबल इंजन सरकार की विफलता का प्रमाण है। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का श्रेय देते हुए कहा कि यह पूरी टीम राजस्थान की सामूहिक मेहनत का परिणाम है।

उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्षदों पर दबाव बनाया तथा धांधली की कोशिश की। इसके बावजूद, शहरी क्षेत्रों में दोनों दलों के वोटों का अंतर एक प्रतिशत से कम रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को करीब पांच प्रतिशत अधिक वोट मिले।

पायलट ने कहा कि कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन और विकास को प्राथमिकता देगी। मनरेगा को दोबारा लागू करने और किसानों को एमएसपी की गारंटी दिलाने के मुद्दे उठाए जाएंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव अभी करीब दो साल दूर हैं। कांग्रेस अगला चुनाव इससे अधिक बहुमत के साथ जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि 2029 में केन्द्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।

केन्द्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन पर सवाल उठाते हुए पायलट ने कहा कि पहले जनगणना और फिर परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रक्रिया पूरी होती है। महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, जबकि महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध नहीं करती। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है।

पंजाब में भाजपा-अकाली दल गठबंधन को अवसरवादिता का उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों दल पहले कृषि कानूनों और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अलग हुए थे, लेकिन अब सत्ता के लिए फिर साथ आ गए हैं। जानकारी के अनुसार, सचिन पायलट ने बुधवार को अपने आवास पर पर ही अपना अधिकांश समय बिताया, क्योंकि प्रदेश भर के कार्यकर्ता उनसे लगातार मिलने के लिए आ रहे थे, इसलिए पायलट बुधवार को दिनभर कार्यकर्ताओं से मुलाकात में ही व्यस्त रहे।

आज बुधवार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर सड़कों पर उतरेंगे। जब तक ज्ञानेश कुमार के पद पर बने रहने के मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकलता, तब तक यह स्पष्ट है कि वे संसद को चलने नहीं देंगे। एक नए और बदले हुए रूप में, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब विरोध प्रदर्शन करने वाली एक मशीनरी बन गई है। राहुल गांधी चाहते हैं कि देशभर में ऐसा ही हो, ताकि यह संदेश जाए कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते और एसआईआर के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता।

'विधानसभा चुनाव में,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तयशुदा परंपरा का पालन करती है और चुनाव से पहले कभी भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं करती।ष्हालांकि उसी कार्यक्रम में जब आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ''कौन है और आगे कौन होगा।''

बांग्लादेश में थानों पर हमलों की घटनायें बढ़ीं, हालात बिगड़े

जनता के जान माल की रक्षा करने वाली पुलिस की खुद की सुरक्षा चिन्ता का विषय बनी

- बांग्लादेश पुलिस एसोसिएशन के अनुसार हमलों में थानों के बुनियादी ढ़ांचे व वाहनों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सरकारी हथियारों के साथ आम लोगों द्वारा जमा कराये गये हथियार भी लूटे जा रहे हैं।

ढ़ाका (बांग्लादेश), 25 नवंबर । देश में अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या की जा रही है। हथकड़ी लगे संदिग्धों को पुलिस हिरासत से छुड़ाया जा रहा है। पुलिस के गश्ती दलों पर हमले हो रहे हैं। सरकारी हथियार लूटे जा रहे हैं और पुलिस थानों को आग के हवाले किया जा रहा है। बिगड़ रहे हालात में लोगों की जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस के सामने खुद की सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय बन गई है। छुटपुट आपराधिक घटनाओं से लेकर राजनीतिक हिंसा तक, पुलिस पर लगातार हो रहे हमले न केवल पुलिसकर्मियों को बड़े खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था लागू करने की क्षमता और अधिकार की भी परीक्षा ले रहे हैं।

''ढ़ाका ट्रिब्यून'' की रिपोर्ट के अनुसार, 17 फरवरी को प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से नौ महीने से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान मार्च से अक्टूबर के बीच पूरे देश में पुलिस पर 400 हमले दर्ज किए गए। जनवरी से अक्टूबर के बीच यह संख्या बढ़ कर 484 हो गई। नवंबर में भी देश के विभिन्न हिस्सों में हमले जारी हैं। हमलों में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। गोपालगंज में दो पुलिस थानों पर हमले किए गए। उन्हें आग लगा दी गई । लूटपाट की गई। अन्य जगहों पर पुलिस की गाड़ियों और परिसरों को निशाना बनाया गया।

गुरुवार को लखनऊ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि मार्च की अनुमति नहीं देना सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के दबाव को दर्शाता है। लखनऊ का यह कार्यक्रम कांग्रेस के देशव्यापी ''संविधान रक्षा मार्च'' का हिस्सा है। इन कार्यक्रमों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी और संविधान की रक्षा की शपथ ली जाएगी। यह अभियान मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ पार्टी के विरोध के बीच चलाया जा रहा है।

इस बीच, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी का घोषणापत्र जारी करने वाले हैं। इसे 'जन-मन का घोषणापत्र' नाम दिया गया है। इसका फोकस सामाजिक न्याय, आरक्षण, लोकतंत्र, रोजगार और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण पर है।

दिन की राजनीतिक गहमागहमी को और तेज करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ''सामाजिक परिवर्तन मोर्चा'' के बैनर तले रमाबाई अम्बेडकर मैदान में अपनी पहली बड़ी संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। दोनों नेताओं ने इसी महीने की शुरुआत में अपने गठबंधन को औपचारिक रूप दिया था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है और राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की गई है। आयोजकों ने ''बहुजन स्वराज संकल्प महारैली'' में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का दावा किया है। इस रैली में दलितों, मुसलमानों और अन्य वंचित समुदायों से जुड़े मुद्दों पर गठबंधन की रणनीति सामने रखी जायेगी। साथ ही, यह गठबंधन खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करेगा।

डीजे बंद कराने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दी। पुलिसकर्मियों ने समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी नहीं माने। आरोप है कि वर्दी और नेम प्लेट पहने होने के बावजूद, पुलिसकर्मियों के साथ बार-बार मारपीट की गई। एसआई रामफूल की शिकायत पर 24 नवंबर को खो नागोरियान थाने में कल्लू हाजी, शौकीन, मिशा, बाबू खान, कबीर खान, इकराम खान, मोहसिन, मिशा पुत्र कबीर और गद्दाम खान सहित, 12 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

प्यूर्टो रिको की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वेनेजुएला की क्लारा वेगास सेकेंड रनर-अप रहीं।

जम्मू-कश्मीर के पांच आतंकवादियों की सम्पत्ति जब्त होगी

- ये पांचों अपनी ज़मीन बेच कर आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहे थे
- पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये लोग हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे। ये संगठन को हथियार, गोला-बारूद और पैसा मुहैय्या कराते थे।

जम्मू, 25 नवंबर। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने रियासी जिले में पांच आतंकवादियों की 28 कनाल और 14.5 मरला जमीन को जब्त करने की मंजूरी दे दी है। जांच में पता चला है कि ये आतंकवादी अपनी संपत्तियों को बेचकर आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहे थे। आदेश के अनुसार, यह मंजूरी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 25 के तहत दी गई है। यह मामला पुलिस स्टेशन महोर में दर्ज एफआईआर नंबर 70/2024 से जुड़ा है। आदेश के अनुसार मोहम्मद कय्यूम उर्फ अब्दुल कय्यूम पुत्र गुलाम मोहम्मद, निवासी शाडोल, तहसील महोर, बशीर अहमद उर्फ मासूम पुत्र कमर दीन, निवासी बड्डर, शौकत अली पुत्र रोशन दीन, निवासी हुंडर, तहसील अरनास, मंजूर अहमद उर्फ मंजूर हुसैन पुत्र मोहम्मद दीन निवासी खंती, तहसील थुरू, और इम्तियाज अहमद पुत्र मोहम्मद मकबूल निवासी थुरू, तहसील थुरू हथियारों और गोला-बारूद का प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान चले गए थे और सीमा पार से इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की कोशिशों में शामिल थे।

जांच से पता चला है कि ये आरोपी अपनी जमीनों को बेचने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ ावा देने के लिए किया जा सके।

राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत

नई दिल्ली, 25 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत दी है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित मामलों को निरस्त करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल कई याचिकाओं के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पास आय ज्यादा संपत्ति है। राहुल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने भी मांग की है। मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया था कि वे राहुल गांधी की संपत्तियों का पता करें।

दिल्ली में दस में से नौ महिलाएं, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुविधाएं, सामाजिक व्यवहार और सरकारी संस्थाओं की नाकामी सार्वजनिक स्थानों तक महिलाओं के आवागमन को प्रभावित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, लैंगिक हिंसा और महिला अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सीक्विन ने अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौंपी हैं।

ये निष्कर्ष दिल्ली-एनसीआर में दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की कई घटनाओं के सामने आने के बीच आए हैं। इनमें आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना भी शामिल है। सितंबर के पहले तीन सप्ताह में इस तरह के कम से कम 13 मामले सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था और अधिकारियों को असुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की पहचान करने तथा सुरक्षा उपाय मजबूत करने का निर्देश दिया था।

सीक्विन ने कहा कि यह अध्ययन अदालत के हस्तक्षेप के बाद किया गया। इसमें लैंगिक हिंसा और महिला अधिकारों के क्षेत्र में संस्था के 17 वर्षों के काम का भी सहारा लिया गया। अध्ययन में यह देखा गया कि सार्वजनिक स्थानों की बनावट और रखरखाव, सामाजिक व्यवहार तथा जवाबदेही की कमी, किस तरह महिलाओं की आने-जाने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है।

सीक्विन की सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक लोरा के. प्रभु ने कहा, ''जब 80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता महिलाओं को यह भी पता नहीं होता कि इन कमियों को दूर करने के लिए कौन-सी नागरिक एजेंसी जिम्मेदार है, तो शहर की व्यवस्था में ही लोगों को बाहर रखने की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि संस्था को उम्मीद है कि उसकी सिफारिशों से ऐसे शहरी सुधार होंगे, जिनके परिणामों को मापा जा सके और जो अलग-अलग लैंगिक वर्गों की जरूरतों को पूरा करें।''

रिपोर्ट में ''राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो'' के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 2024 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,396 मामले दर्ज किए गए थे। यह भारत के 19 प्रमुख महानगरों में सबसे बड़ी संख्या थी।

रिपोर्ट में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी के बीच अंतर को भी उजागर किया गया है। 2023-24 में दिल्ली में महिलाओं की लेबर फोर्स पार्टीसिपेशन दर 14.5 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों के लिए यह 54 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं और आने-जाने पर लगी पाबंदियों का असर महिलाओं के रोजगार के अवसरों तक पहुंच पर पड़ता है। हालांकि, इन आंकड़ों से दोनों के बीच सीधे कारण-परिणाम संबंध साबित नहीं होता।

सीजेपी के सौरभ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है।

उल्लेखनीय है कि सौरभ दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोका गया था। 23 नवंबर को देर रात एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की जांच के दौरान उनको रोका गया था। उनके खिलाफ

नागरिकता और पासपोर्ट को लेकर एक मामला मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है। सौरभ दास का कहना था कि वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेक्चर देने जा रहे थे।

क्रॉस वोटिंग और सियासी खींचतान के बावजूद कांग्रेस ने 24 जिलों में जिला प्रमुख बनाए

मात्र 5 सीटों पर स्पष्ट बहुमत था, लेकिन भाजपा ने भी 10 सीटों पर कब्जा जमाया

-कार्यालय संवाददाता-

- सीकर और झुंझुनूं में भीतरघात नहीं रोक पाई कांग्रेस की जीत, बीकानेर में निकिता डूडी बनीं जिला प्रमुख।
- नागौर में रालोपा और बांसवाड़ा-डूंगरपुर में बीएपी का कब्जा।

जयपुर, 25 नवम्बर। राजस्थान के 37 जिला प्रमुखों के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 जिला परिषदों में अपना परचम फहराया, जबकि भाजपा 10 जिलों में ही जिला प्रमुख बना सकी। चुनाव में कांग्रेस को सीकर और झुंझुनूं जैसे जिलों में क्रॉस वोटिंग के बावजूद जीत मिली, वहीं बीकानेर में निकिता डूडी की जीत ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान पर विराम लगा दिया। दूसरी ओर, भाजपा को प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी के सदस्यों का समर्थन मिला। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बांसवाड़ा व डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी ने जिला प्रमुख पद हासिल किया। नतीजों ने प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस की मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर में कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता गठाला 37 वोट लेकर विजयी रहीं, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 16 वोट मिले। यहां कांग्रेस के तीन वार्ड सदस्यों की क्रॉस वोटिंग की चर्चा रही, लेकिन इससे जीत प्रभावित नहीं हुई। झुंझुनूं में भी कांग्रेस प्रत्याशी कोमल भंवरिया ने जीत दर्ज की। यहां भाजपा प्रत्याशी को 12 वोट मिले।

बीकानेर में दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं। यहां पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल की बेटी सरिता चौहान ने कांग्रेस से दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने निकिता डूडी को सिंबल दिया। इसके विरोध में सरिता चौहान ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, इसके बावजूद निकिता चुनाव जीत गईं। ब्यावर में भी स्पष्ट बहुमत नहीं होने के बावजूद कांग्रेस, प्रत्याशी ममता गुर्जर ने जीत दर्ज की।

जिले-वार कांग्रेस के निर्वाचित जिला प्रमुख इस प्रकार हैं - जयपुर में यशवीर सूरा, जालौर में आशु देवासी, चित्तौड़गढ़ में रत्नीदेवी, टोंक में अलका बैरवा, सलूंबर में पुष्पा देवी, फलोदी में यशवंत कंवर, बूंदी में हंसा गुर्जर, बीकानेर में निकिता डूडी, बाड़मेर में गफूर अहमद, सीकर में सुनीता गठाला, झुंझुनूं में कोमल भंवरिया, राजसमंद में सुंदर देवी, जोधपुर में प्रमिला चौधरी, ब्यावर में ममता गुर्जर, हनुमानगढ़ में रेनू जांगू, धौलपुर में अनिशा कुमारी, भरतपुर में रेनू बाला और अलवर में अनीता मीणा। बालोतरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला भील विजयी रहीं।

भाजपा के जिले-वार निर्वाचित जिला प्रमुख इस प्रकार हैं - अजमेर में पूजा भंसाली, पाली में सीता बावरी, उदयपुर में हिम्मत सिंह झाला, डीग में रेनू सिंह, चूरू में कनिका सिंह राठौड़, खैरथल-तिजारा में इंद्रजीत यादव और प्रतापगढ़ में हकरी देवी। प्रतापगढ़ में भाजपा को भारत आदिवासी पार्टी के वार्ड सदस्यों का समर्थन मिला। यहां कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा के सामने भाजपा का जिला प्रमुख बनवाने की चुनौती थी।

कुचामन-डीडवाना जिला परिषद में दोनों पक्षों को समान वोट मिलने पर पर्ची से फैसला हुआ। एक बालिका द्वारा निकाली गई पर्ची में भाजपा प्रत्याशी बुद्धाराम का नाम आने पर उन्हें जिला प्रमुख घोषित किया गया।

नागौर जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत के चलते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पांचूराम जिला प्रमुख चुने गए। बांसवाड़ा में भाजपा के समर्थन से भारत आदिवासी पार्टी की रीना रावत और डूंगरपुर में बीएपी के अनुतोस रोत जिला प्रमुख निर्वाचित हुए।

पूर्व आईएएस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने यह आदेश सुबोध अग्रवाल व अन्य की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए।

गौरतलब है कि सुबोध अग्रवाल को एसीबी ने 9 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908